राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2718

11 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

देश में प्रति-व्यक्ति इस्पात खपत

2718. श्री परिमल नथवानीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में प्रति-व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का घरेलू इस्पात खरीदने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो देश में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए संबंधित मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ की गई बातचीत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 तैयार की है जिसमें प्रति व्यक्ति इस्पात खपत के वर्ष 2030-31 तक बढ़कर 160 कि.ग्राम हो जाने की परिकल्पना की गई है। इस दिशा में इस्पात प्रधान ढांचों, सरकारी परियोजनाओं में जीवनचक्र लागत विश्लेषण पर विचार करने के लिए नए जीएफआर नियम 136(i)(iii) प्रविष्ट करके इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने, कार्यशालाओं के आयोजन, 'इस्पाती-इरादा' नामक समन्वयात्मक ब्रांडिंग अभियानों, देश में कैपिटल गुड्स विनिर्माण तथा इस्पात संयंत्रों के निकट इस्पात कलस्टरों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 'मेक-इन-इंडिया' पहल तथा ग्रामीण एवं शहरी आवासीय योजनाओं जैसे भवन एवं निर्माण क्षेत्र और अवसंरचना विकास क्षेत्र से देश में इस्पात की मांग और खपत को बल मिला है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 57.6 कि.ग्राम से बढ़कर 74.1 कि.ग्राम हो गई है। इसके अतिरिक्त, अगले पांच वर्षों के दौरान अवसंरचना विकास के लिए 100 लाख करोड़ रूपये के निवेश की सरकार की योजना से देश में इस्पात की मांग तथा प्रति व्यक्ति खपत बढ़ेगी।

(ख) और (ग): सरकार की स्वदेशी विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद खरीद (डीएमआई एंड एसपी) नीति सरकारी खरीद में सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों से स्वदेशी रूप से विनिर्मित इस्पात उत्पादों को वरीयता देने को अनिवार्य बनाती है। स्वदेशी इस्पात की खरीद के लिए पीएसयू हेतु प्रोत्साहन नीति की घोषणा किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****